जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 107 प्रभात चूरू, मंगलवार 13 अगस्त, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच की भूमिका पर तलवारें खिंची मोदी सरकार व विपक्ष में

सरकार का कहना है कि श्रीमती बुच को कठघरे में खड़ा करके विपक्ष उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया है, जो भारत में कोई "इकोनॉमिक इन्वेस्टमैंट" नहीं होने देना चाहता

- सरकार का यह भी कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने श्रीमती बुच व अडानी ग्रुप की सांठ-गांठ का आरोप लगाया है, के मालिक हंगरी में जन्मे अमेरिकी इन्वेस्टर सोरोस हैं तथा सोरोस शुरु से भारत, नरेन्द्र मोदी व भाजपा के खिलाफ प्रोपैगेंडा करते रहे हैं।
- दूसरी ओर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है श्रीमती बुच, सेबी की अध्यक्ष के रूप में सदा अडानी ग्रुप के बचाव में रही हैं।
- तथा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में प्रकाशित सबूत व आरोपों, जिनकी पुष्टि 40 निष्पक्ष व स्वतंत्र मीडिया ग्रुप्स ने भी की है, की अनेदखी करती रहीं हैं, सेबी की अध्यक्ष के रूप में।
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि श्रीमती बुच ने इस बात को भी कभी सार्वजनिक नहीं किया कि उनके पास उस कंपनी में शेयर थे जिसे अडानी ग्रुप ने काम में लिया था, अपना ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिये।
- सेबी के नियमों के अनुसार, सेबी के किसी भी अधिकारी का उस केस में थोड़ा बहुत भी "इन्टरेस्ट" है, जिसकी सेबी जाँच-पड़ताल कर रही है या करने की सोच रही है तो उस अफसर के लिए "अपना इन्टरेस्ट" सार्वजनिक करना या उस जाँच से अपने को अलग कर लेना अनिवार्य होता है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अगस्त। जैसी कि उम्मीद थी, ताजातरीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच साफ तौर पर आमने सामने आ गए हैं। ज्ञातव्य है कि इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एस.ई.बी.आई. (सेबी) प्रमुख माधवी पुरी बुच तथा उनके पति धवल बुच की अडानी के घोटाले में गहरी लिप्तता है तथा अडानी के उस गुमनाम ऑफशोर फंड में बुच-युगल की हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के घोर समर्थक इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रहित के खिलाफ एक साजिश के रूप में देख रहे हैं।

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुये यह दावा किया गया है कि बुच दम्पति आई.पी.ई. प्लस फंड, जो एक ऑफशोर (देश से बाहर स्थित) फर्म है, में शामिल है तथा यह फर्म संवीक्षा (स्क्रूटनी) में आ गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी का भाई, विनोद (कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर) के हिस्से के रूप में करता था, जो मनी-लॉन्डरिंग के लिये अनेक ऑफशोर फंड्स से जुड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. पेपर लीक केस, सुप्रीम कोर्ट ने एस.एल.पी. खारिज की

जयपुर, 12 अगस्त (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने एस.आई. भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एस.ओ.जी. की ओर से की गई आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई को सही माना है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इन्कार करते हुए उनकी स्पैशल

- सुप्रीम कोर्ट ने एस.आई. पेपर लीक केस के ट्रेनी आरोपियों की गिरफ्तारी को सही माना और आरोपियों को जमानत देने से इन्कार करते हुए उनकी एस.एल.पी. खारिज कर दी।

लीव पिटिशन (एस.एल.पी.) खारिज कर दी। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मिथ्थल की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी सुभाष विश्नोई व अन्य की एस.एल.पी. पर दिए।

खंडपीठ ने कहा कि आरोपियों का अपराध एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ न होकर पूरे समाज के खिलाफ है। आरोपियों ने लाखों प्रतिभाशाली लोगों की भावनाओं के साथ खेला है और ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस.ओ.जी. पहले आरोपियों को पूछताछ के लिए लाई थी और उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ये माधवी पुरी बुच आखिर हैं कौन?

सेबी की वर्तमान अध्यक्ष, श्रीमती बुच 2017 से सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल में सेबी के बोर्ड की सदस्य बनीं, तदोपरान्त सेबी की पहली महिला अध्यक्षा बनीं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अगस्त। सिक्यूरीटीज़ एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, जो कि अमेरिका रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के कारण विवादों के घेरे में हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं।

वर्ष 1966 में जन्मी माधवी अप्रैल 2017 से ही सेबी के पूर्व अध्यक्ष अजय त्यागी के साथ सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रुप में काम कर चुकी हैं। वे पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें प्राइवेट सैक्टर से लाकर इस पोस्ट पर लगाया गया था।

वे पहली श्ख्स थीं, जो प्राइवेट सैक्टर से आईं और उन्हें सेबी का प्रमुख बनाया गया। इस पर काफी विवाद भी उठा और पूछा गया कि आखिर उन्हें इस सर्वोच्च पद पर लाने के पीछे किसका हाथ है।

इसी के साथ यह कहा जाना भी आवश्यक है कि सेबी अध्यक्ष के रुप में माधवी ने सिस्टम को सुचारु रुप से चलाने में और संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उसका व्यवसायीकरण

- श्रीमती बुच, पहली व्यक्ति हैं, जो प्राइवेट सैक्टर से सेबी के सर्वोच्च पद पर नियुक्त हुई हैं।
- श्रीमती बुच ने सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से मैथमैटिक्स (गणित) में ग्रेजुएशन (स्नातक) की पढ़ाई की तथा इसके बाद आई.आई.एम. अहमदाबाद से एम.बी.ए. की शिक्षा ग्रहण की।
- अठारह वर्ष की उम्र में धवल बुच से मंगनी की, उस समय उनके भावी पति, बहुराष्ट्रीय कंपनी युनिलीवर में निदेशक थे। 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद दोनों की शादी हुई
- वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं तथा सेबी में कई नये टैक्नोज़िकल सिस्टम शुरु करवाये हैं। सेबी में "कॉरपोरेट कल्चर" (कोरपीटाइज़ेशन) की प्रक्रिया उन्होंने आरम्भ की।
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट में माधवी पुरी बुच व उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप के शेयर के दाम बेहिसाब तरीके से बढ़वाने में मदद करने का आरोप लगा हुआ है।

करने में अहं भूमिका निभाई थी।

माधवी पुरी बुच ने मुम्बई के फोर्ट कॉन्वैन्ट और दिल्ली के कॉन्वैंट आफ जीसस एण्ड मैरी से स्कूली शिक्षा पूरी की और दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से उन्होंने गणित विषय में ग्रेजुएशन किया और अहमदाबाद आई.आई.एम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा फिर से मंत्री पद संभाल सकते हैं

पिछले दो दिन से आपदा प्रबंधन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं डॉ. किरोड़ी

- डॉ. किरोडी, भजनलाल सरकार में ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन मंत्री के पद पर ही थे।
- मंगलवार को भी डॉ. किरोड़ी पूर्वी राजस्थान के जिलों का दौरा करेंगे।
- भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा कि डॉ. किरोड़ी जल्दी ही मंत्री पद की जिम्मेवारी संभालेंगे।

जयपुर, 12 अगस्त (का.सं.)। भजनलाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से मंत्री पद संभाल सकते हैं, जिसके संकेत अब मिलने लगे हैं। पिछले दो दिनों से किरोड़ीलाल मीणा प्रदेश में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वे भजनलाल सरकार में ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी विभाग का कामकाज नहीं देख रहे थे। लेकिन अब अचानक किरोड़ी आपदा प्रबंधन विभाग में सक्रिय हुए हैं। रविवार को उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार से प्रदेश में भारी बारिश से उपजी स्थिति के संबंध में वार्ता की। वहीं, मंगलवार को किरोड़ी पूर्वी राजस्थान के जिलों में जलभराव वाले इलाकों का दौरा करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा कि किरोड़ी जल्द कामकाज संभालेंगे, उन्होंने भावनात्मक रूप से मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

गौरतलब है कि किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनावों में दौसा सीट नहीं जीतने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। चुनाव में भाजपा दौसा लोकसभा सीट हार गई, जिसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसका खुलासा खुद किरोड़ी ने 4 जुलाई को जयपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया था।

उसके बाद से ही किरोड़ी विभाग का कामकाज नहीं देख रहे थे। लेकिन, पिछले दो दिन से किरोड़ी प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रविवार को किरोड़ी ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति के बारे में वार्ता की। इसके अलावा, मंगलवार को वे महुवा, वैर, (श्रीनगर) बयाना, हिण्डौन, करौली, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में जलभराव वाले इलाकों के दौरे पर रहेंगे। इसकी जानकारी उन्होने अपने सोशल मीडिया अकाउन्ट एक्स पर भी दी।

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के पिछले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंघानिया वि.वि. पर कार्रवाई क्यों नहीं- हाई कोर्ट

जयपुर, 12 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउन्सिल (एन.एम.सी.) से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित करने वाली झुंझुंनू की सिंघानिया युनिवर्सिटी के खिलाफ

- नैशनल मैडिकल काउन्सिल से मान्यता लिए बिना ही एम.बी.बी.एस. कोर्स संचालित कर रहे झुंझुनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय पर कार्यवाही नहीं करने को हाई कोर्ट ने गंभीर माना और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

शिकायत मिलने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं करने को गंभीर माना है। इसी क्रम में अदालत ने अतिरिक्त मुख्य उच्च शिक्षा सचिव को मंगलवार को उपस्थित होकर यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा व विपक्ष यू.पी. के बाय इलैक्शन ऐसे लड़ रहे हैं, जैसे अस्तित्व की लड़ाई हो

10 सीटों पर उपचनुाव हो रहे हैं उनमें से सात भाजपा व सहयोगी दलों के पास थी तथा बाकी तीन पर सपा आदि का कब्जा था

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अगस्त। ऐसा प्रायः देखने में नहीं आता है कि विधानसभा उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण मान लिये जायें, जितने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के आगामी उपचुनाव मान लिये गये हैं। लोकसभा चुनाव में लगे आघात के जख्मों को अभी भी सहला रही भाजपा ने शनिवार को राज्यव्यापी "तिरंगा यात्रा" शुरु कर दी, जिसका उद्देश्य हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद के उद्घोष को और अधिक सशक्त करना है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "मिशन-20" लॉन्च कर ही दिया है, जिसके अन्तर्गत सभी दस चुनाव क्षेत्रों में से प्रत्येक की चुनाव व्यवस्था की देख-रेख के लिये दो-दो मंत्री लगा दिये गये हैं।

इसी प्रकार, कांग्रेस ने एक महीने का प्रचार अभियान शुरु कर दिया है, जो जातिगत जनगणना की उसकी माँग तथा वक्फ संशोधन विधेयक पर उसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर केन्द्रित है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, वह अपने पी.डी.ए. मुद्दे पर जोर देने के लिये पूरे राज्य में पदयात्रा आयोजित कर रही है।

- पर, इस बार उपचुनाव में दोनों राजनीतिक ग्रुप अपनी पुरानी सीट पर जीतने के प्रयास में ही नहीं हैं, बल्कि 10-0 का स्कोर चाहते हैं।
- भाजपा लोकसभा चुनाव में पायी असफलता का कलंक धो देना चाहती है।
- इंडिया गठबंधन 10-0 का स्कोर हासिल कर यह जताना चाहता है कि लोकसभा की सफलता कोई अपवाद नहीं थी, बल्कि जनता के मूड का सही मापदंड था और यह मूड अभी भी बरकरार है।
- कांटे की टक्कर फैज़ाबाद जिले की मिल्कीपुर सीट पर है। लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट पर सपा जीती थी, यह भाजपा के मुंह पर चपत था, क्योंकि इस सीट के केन्द्र बिन्दु अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया था, भाजपा ने।

इन 10 सीटों में से, भाजपा ने 2022 के चुनाव में 5 सीटें जीती थीं तथा इसके दो मित्र दलों ने एक-एक सीट जीती थी। शेष सीटें सपा के खाते में गई थीं। इन उपचुनावों के बारे में एक विशेष पहलू यह है कि 2022 के चुनावों में प्राप्त सीटों को अपने पास बनाये रखने की लड़ाई के बजाय, दोनों ही गठबंधन- एन.डी.ए. तथा इंडिया इन उपचुनावों को सभी चुनावी लड़ाइयों की मां मानते हुये लड़ रहे हैं। दोनों ही गठबंधन इन उपचुनावों का परिणाम 10-0 रखने के लिये संकल्पित हैं। जाहिर है, दोनों ही गठबंधनों के लिये इन उपचुनावों का राजनैतिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। इन उपचुनावों के नतीजे से ही यह तय होगा कि योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे अथवा नहीं। वहीं, इंडिया ब्लॉक के लिये ये चुनाव इस बात का संकेत देंगे कि उसे लोकसभा में मिला लाभ वास्तविक तथा स्थायी था अथवा नहीं।

इन 10 सीटों में, सबसे ज्यादा महत्व मिल्कीपुर सीट को दिया जा रहा है। भाजपा इस सीट को जीतने के लिये

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना के कैब चालकों ने आंध्र के टैक्सी चालकों को भगाने की मुहिम शुरु की

तेलंगाना कैब ड्राइवर्स का मत है कि आंध्र के टैक्सी चालकों की वजह से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अगस्त। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के लोग तेलुगूभाषी हैं, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आंध्र के कुछ लोग टैक्सियां चला रहे हैं। आजीविका का मृद्दा गर्माने के कारण इन टैक्सी वालों से आंध्रप्रदेश जाने के लिए कहा जा रहा है।

तेलंगाना मूल के कैब चालक इस बात को लेकर परेशान है कि आई.टी. हब हैदराबाद में बाहर के वाहनों की बाढ़ आई हुई है और ये लोग उनकी आजीविका छीन रहे हैं।

आंध्रप्रदेश के विभाजन से एक लम्बे जनांदोलन के बाद दस वर्ष पूर्व तेलंगाना और आंध्रप्रदेश और 2 जून 2024 के एक समझौते के अनुसार हैदराबाद अब दोनों राज्यों की एक राजधानी नहीं रहा है और तभी से तेलंगाना के टैक्सी ड्राइवर आंध्र के टैक्सी ड्राइवर्स को राज्य से बाहर निकालने का दबाव बना रहे हैं।

स्थानीय कैब यूनियन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह हैदराबाद में चलने वाले अन्य राज्य के वाहनों के संचालन को रैग्युलेट करे। वास्तव में, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडू के वाहनों का परमिट लैप्स हो जाने के बावजूद ऐप आधारित शेयरिंग सर्विसेज तथा सॉफ्टवेयर फर्म्स के लिए कार्य करते पाया गया है।

स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर्स ने कहा है कि बाहर के राज्यों की कैब्स में से ज्यादातर आंध्रप्रदेश की हैं और परिवर्तन विभाग को बाहर के वाहनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

- तेलंगाना के कैब ड्राइवर्स की यूनियन ने राज्य सरकार से व अन्य राज्यों के कैब ड्राइवर्स के काम काज पर सख्ती बरतने का आग्रह किया, पर, उनका निशाना आंध्र के कैब ड्राइवर्स हैं, जो उनकी ही तरह तेलुगू भाषी हैं।
- दस साल पहले जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था और तेलंगाना व आंध्र दो राज्य बने थे तब हैदराबाद को दस साल के लिए दोनों राज्यों की राजधानी करार दिया गया था, और तब से ही दोनों तेलुगू भाषी राज्यों के कैब ड्राइवर्स अपना-अपना काम कर रहे थे।
- पर, समझौते के अनुसार, 2 जून 2024 से हैदराबाद संयुक्त राजधानी नहीं रह गया है, अब यह सिर्फ तेलंगाना की राजधानी है। तब से ही तेलंगाना के कैब ड्राइवर्स आंध्र के टैक्सी चालकों को भगाने पर तुले हैं।

अब, हैदराबाद में कार्यरत आंध्र के टैक्सी ऑपरेटर्स आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने यूनियन के नेताओं से बात कर अनुरोध किया है कि आंध्र के लोगों को भी हैदाराबाद में काम करने दिया जाए। इस अनुरोध पर तेलंगाना की कैब ड्राइवर्स यूनियन ने कहा कि वह आंध्र के कैब ड्राइवर्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका विरोध एग्रीगेटर कम्पनियों से हैं जो अवैध रूप से सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं।

"तेलंगाना गिग एण्ड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन" के अध्यक्ष शाईक सलाउद्दीन ने कहा कि "तेलंगाना में संचालित अन्य राज्य के वाहन राजकोष को प्रभावित करते हैं। त्योहारों के सीज़न में निजी वाहनों द्वारा अवैध कैब सर्विसेज बढ़ जाती हैं जिससे पंजीकृत कैब ड्राइवर्स का कारोबार प्रभावित होता है तथा यात्री सुरक्षा का भी जोखिम रहता है।"

आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तेलंगाना की कैब ड्राइवर्स यूनियन से अपील की है कि वे अपने साथी तेलुगू भाषी लोगों को अपने साथ काम करने की मंजूरी दें क्योंकि दोनों तेलुगू भाषी राज्यों के विकास के लिए उनमें एकता जरूरी है। आंध्र के कैब ड्राइवर्स को हैदराबाद से चले जाने की बात कहना अनुचित है। उन्होंने तेलंगाना के कैब ड्राइवर्स से अनुरोध किया कि वे आंध्रप्रदेश के अपने भाईयों के साथ संवेदनशीलता से काम लें क्योंकि उन्हें अपने स्थान से हटाने का मतलब होगा 2 हजार परिवारों की आजीविका छीनना।

पवन कल्याण ने यह भी कहा कि वह इस समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे और तेलंगाना सरकार के संबंधित लोगों से बात करेंगे। तेलुगू भाषी दोनों राज्यों को परस्पर सहयोग की आवश्यकता है।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सुरक्षा में चूक

अजमेर, 12 अगस्त (कासं)। एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी जब अधिकारियों की बैठक लेने अजमेर के जिला कलैक्ट्रेट सभागार पहुंचीं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी करते हुए एक युवक बैठक में पहुंच गया। बैठक में तीनों जिले के एस.पी. और कलैक्टर सहित

- अजमेर कलैक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान एक अज्ञात युवक दौड़ता हुआ आया और सभागार में घुस गया, पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है।

अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सुरक्षाकर्मियों ने बाद में युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है।

जिला कलैक्ट्रेट के सभागार में सोमवार को जब उपमुख्यमंत्री दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)